**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.1568**

**दिनांक 4 मार्च, 2020**

**कच्चे तेल के उत्पादन में निजी भागीदारी**

**1568. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन में निजी कंपनियों द्वारा निवेश में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क)  से (ग) : सरकार ने निजी कंपनियों द्वारा कच्‍चे तेल के उत्‍पादन में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक परिवर्तनकारी नीतिगत उपाय/पहलें की हैं जिनमें निम्‍नलिखित शामिल हैं :

i. हाइड्रोकार्बन खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदा (पीएससी) व्‍यवस्‍था के तहत रियायतों, अवधि बढ़ाए जाने और स्‍पष्‍टीकरणों के लिए नीति, 2014

 ii.     खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015

iii.     हाइड्रोकार्बन अन्‍वेषण और लाइसेंसिंग नीति, 2016

iv.     उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं की अवधि बढ़ाने के लिए नीति, 2016 और 2017

v.     नेशनल डाटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017

 vi.     तलछटीय बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन

 vii.     हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुन: आकलन

  viii. एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी ब्‍लॉकों में उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं की कार्य प्रणाली को व्‍यवस्थित बनाने के लिए नीतिगत ढांचा, 2018

ix. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्‍साहित करने के लिए नीति, 2018

x. मौजूदा उत्पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं, कोल बेड मिथेन संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्‍वेषण और दोहन हेतु नीतिगत ढांचा, 2018

xi. इसके अलावा, सरकार ने अन्‍वेषण कार्यकलाप बढ़ाने, तलछटीय बेसिनों के गैर-अन्‍वेषित/गैर-आबंटित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने और मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस के घरेलू उत्‍पादन को बढ़ाने के उद्देश्‍य से फरवरी, 2019 में अन्‍वेषण और लाइसेंसिंग नीति में प्रमुख सुधारों को अनुमोदित कर दिया है। नीतिगत सुधारों का लक्ष्‍य अन्‍य बातों के साथ-साथ कार्य कार्यक्रम को और ज्‍यादा प्राथमिकता देते हुए अन्‍वेषण कार्यकलापों को बढ़ाना, सरकार के साथ बगैर किसी उत्‍पादन अथवा राजस्‍व हिस्‍सेदारी के श्रेणी II और III के तलछटीय बेसिनों के संबंध में अन्‍वेषण ब्‍लॉकों की बोली लगाना शामिल है।  इसके अलावा, किए जाने वाले सुधारों में राजकोषीय और संविदागत शर्तों को सरल बनाना, राजकोषीय प्रोत्‍साहन दे कर खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करना, विपणन और मूल्‍य निर्धारण की आजादी देते हुए गैस उत्‍पादन बढ़ाना,  नामांकन क्षेत्रों में उत्‍पादन बढ़ाने की पद्धतियों हेतु सहयोग तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए राष्‍ट्रीय तेल कंपनियों को काम करने की और ज्‍यादा आजादी देना है। अनुमोदन की प्रक्रियाओं को व्‍यवस्‍थि‍‍त करना तथा इलै‍क्‍ट्रोनिक एकल खिड़की व्‍यवस्‍था के साथ आसानी से कारोबार बढाना भी नीतिगत सुधारों का एक महत्‍वपूर्ण पहलू है।

\*\*\*\*